

सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.।।।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग

\*\*\*

नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को नवम्बर, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम चौधरी

(अरूप श्याम चौधरी)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के प्रधान सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आ.का.) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. सुश्री मीरा स्वरूप, एएस एवं एफए (वित्त)।
14. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आ.का.वि.
15. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आ.का.वि.।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।  
वरिष्ठ सलाहकार (सीएवंसी/एफएसएलआर/एफएस और सीएस)/ संयुक्त सचिव (बीसी एवं आईआईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/ सलाहकार (आईआईआर) सीएए।
18. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एवं सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
19. गार्ड फाइल - 2021 ।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

\*\*\*\*

विषय: नवंबर, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. वृहद-आर्थिक सिंहावलोकन

भारत की आर्थिक सुधार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही (Q) (जुलाई-सितंबर) में महामारी से पहले के अपने उत्पादन स्तर को पार करने के लिए और गति प्राप्त की। संक्रमण के मामलों में गिरावट, प्रतिबंधों में ढील और तेजी से टीकाकरण कवरेज ने रिकवरी को सहयोग किया गया था। 2021-22 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 2020-21 की दूसरी तिमाही की तुलना में 8.4% रहने का अनुमान है। 2021-22 के पहली छमाही (क्यू1+क्यू2) में वृद्धि तदनुसार 2020-21 के पहली छमाही की तुलना में 13.7% है। इसके साथ, महामारी से पहले, वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में उत्पादन का 95.6% से अधिक रिकवर हो गया है। मांग पक्ष पर, 2021-22 की पहली छमाही में महामारी से पहले के स्तर की वसूली, निर्यात में 113% पर सबसे महत्वपूर्ण है। निजी खपत में पहली छमाही में रिकवरी 92.3% के करीब है। आपूर्ति पक्ष पर, 2021-22 की पहली छमाही में महामारी से पहले के स्तर की वसूली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 108% पर सबसे महत्वपूर्ण है और विनिर्माण में वसूली लगभग 99.9% है। खनन भारी बारिश के कारण हुए व्यवधान के कारण 2021-22 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में क्रमिक रूप से 14.0% कम हो गया। क्षेत्रवार विकास दर अनुबंध में दी गई है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

i. 1,2,5,10 और 20 रुपये के स्मारक सिक्के जारी करने हेतु दिनांक 08.11.2021 को राजपत्रित अधिसूचना सं.जी.एस.आर.सं. 783(ई) जारी किया गया है।

ii. हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर शताब्दी समारोह के अवसर को मनाने के लिए 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी करने हेतु दिनांक 18.11.2021 को राजपत्रित अधिसूचना सं.जी.एस.आर.सं. 806(ई) जारी किया गया है।

iii. नवंबर, 2021 के महीने के दौरान बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ कुछ मामलों में निम्नलिखित ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और बातचीत की गई:

हस्ताक्षरित ऋण:

क) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन परियोजना के तहत 'शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को मजबूत करने' के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ ऋण समझौता।

ख) आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन (एसएएलटी) परियोजना को समर्थन देने के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक (पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक) के साथ ऋण समझौता;

ग) औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम - उप कार्यक्रम-I के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ ऋण समझौता;

घ) अगरतला शहर शहरी विकास परियोजना के लिए 61 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ ऋण समझौता;

परक्रामित ऋण:

क) राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर का वित्तपोषण तय हुआ;

ख) सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर का वित्तपोषण तय हुआ;

ग) असम कौशल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए 112 मिलियन अमरीकी डालर का वित्तपोषण तय हुआ।